**कोविड-19 का प्रभाव कम करने और भविष्य में ऐसी आपदा रोकने के लिए मांग पत्र**

भारत एक अभूतपूर्व मानवीय संकट से गुज़र रहा है। कोविड-19 की पहली लहर में हज़ारों जानें गवाने के बाद भी केंद्र सरकार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने में नाकाम रही है। संक्रमण को रोकने के लिए हुई तालाबंदी व अपर्याप्त राहत के कारण अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों मजदूरों का जीवन और आजीविका बाधित हुई और उनकी खाद्य एवं आर्थिक असुरक्षा और बदतर हुई है। सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण और न्यूनतम आय सुनिश्चित कराने की बजाय सरकार अपनी छवि बचाने में लगी है. इसके लिए सरकार उसकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर मुकदमे चला रही है, सोशल मीडिया पर ज़मीनी हक़ीक़त दिखाने पर रोक लगा रही है और "सकारात्मकता" अभियानों से लोगों को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। और तो और, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है लिए कोविड-19 के बचाव और रोकथाम के लिए इकत्रित की गई राशि व अन्य सहायता का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है।

कोविड-19 के भीषण प्रभाव को रोकने, तथा भविष्य में ऐसे संकट से बचने के लिए जन अभियान केंद्र सरकार से निम्न मांगे करते हैं:

**स्वास्थ्य सेवाएं**

* कोविड-19 के सभी मरीज़ों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण रोकथाम (अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन आदि के साथ)।
* टेस्टिंग, कौनटैक्ट ट्रेसिंग और आईसोलेशन सेंटर की पर्याप्त सुविधाएं।
* निःशुल्क और सार्वभौमिक टीकाकरण, अधिक असुरक्षित लोगों को प्राथमिकता देते हुए।
* निजी क्षेत्र द्वारा लोगों के शोषण पर तुरंत रोक लगे व यह एक दंडनीय अपराध बने।
* सभी फ्रंटलाइन कर्मियों, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों, को पूरी सुरक्षा दी जाए और साथ में उन्हें पर्याप्त व समय पर मानदेय मिले।

**खाद्य सुरक्षा**

* अगले छः महीनों तक कम से कम जन वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाए, और हर व्यक्ति को प्रति माह कम से कम 5 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल और 800 ग्राम खाद्य तेल मिले।
* आंगनवाड़ियाँ छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पौष्टिक आहार दें (जिसमें अंडा, दाल और तेल शामिल हो)।
* शहरों में पका व पौष्टिक भोजन मिले।
* सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि कम से कम न्यूनतम मज़दूरी की आधी हो और सभी बुजुर्गों, एकल महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को हर महीने मिले।

**आय सुरक्षा**

* महामारी के अंतराल में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सार्वभौमिकरण हो, जिससे सभी परिवारों को किसी भी सदस्य की मृत्यु के लिए मुआवज़ा मिले।
* नरेगा में काम की गारंटी कम से कम 200 दिन प्रति वर्ष हो और मज़दूरी न्यूनतम कृषि मज़दूरी से कम न हो।
* शहरी रोजगार गारंटी को जल्द ही शुरू किया जाए।

**जवाबदेही**

* समय पर लोगों को सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकारी निर्णयों, कार्यों व योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता की ज़रूरत है (PM CARES व अन्य देशों से मिली मदद में भी).
* सभी सेवाओं के क्रियान्वयन का समय समय पर अंकेक्षण हो.
* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में वर्णित शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू किया जाए.
* हेल्पलाइनों में लोगों की शिकायतों का समयबद्ध रूप से निवारण हो.
* इस संकट के समय सभी राज्य खाद्य आयोग बहुत सुचारु रूप से चले.

*इन मांगों पर दबाव डालने के लिए जून 2021 को जन आन्दोलन एक अभियान चलाएंगे. अभियान की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए ट्विटर पर @rozi\_roti को फौलो करें. अभियान से जुड़ने के लिए आयशा (9716048979) या राज शेखर (7985946875) को संपर्क करें.*